

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 37/2021

पंजीयन दिनांक 22.06.2021

पारसनाथ पिता शंकरनाथ जाति योगी उर्फ जोगी निवासी भोपालसागर तहसील भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय-

- (1). जितेन्द्र पिता पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). विशाल पिता पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). मधुमती पत्नी पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
- (4). सीमानाथ पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
- (5). सोनिया पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
- (6). निशा पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी निवासी हाल सेती चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

- (1). चन्दर रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (2). भंवरबाई पत्नी बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (3). दरियाकंवर पुत्री बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (4). फूलकंवर पुत्री बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (5). नरेन्द्र रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (6). महेन्द्र रावल पिता बाली रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (7). शान्ता देवी पत्नी मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।


राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

- (8). प्रवीण रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (9). विमलेश रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (10). पूजा पुत्री मोहन रावल जाति जोगी नाबालिग बयिलायत माता शान्ता देवी पत्नी मोहन रावल जाति जोगी निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (11). रेखा पुत्री पारसनाथ उर्फ पार्श्वनाथ जाति योगी उर्फ जोगी निवासी हाल 50 जो. एस. ग्रीन लैण्ड हार्ट फोर्ट, कैम्प केन्ट, काउन्टी यू.के.(लन्दन)।
- (12). तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
- (13). उप पंजीयक देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

-रेस्पोंडेन्टगण



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्रकरण संख्या 63/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2018

- उपस्थित वक्त बहस-
- (1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांतगण
 - (2). रेस्पोंड संख्या 1 से 4 व 7 से 11- बावजूद सूचना अनुपस्थित
 - (3). अमित नाहर-अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टगण संख्या 5 व 6
 - (4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 12,13

निर्णय

दिनांक 07.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 41 मे दर्ज आराजी संख्या 42/1 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 42/3 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 42/4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 43 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 77 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 79 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 211 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 212 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 213 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 3 बिस्वा आराजी चाह कुल किता 11 कुल रकबा 54 बीघा 5 बिस्वा भूमी रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर दर्ज रेकॉर्ड हे। रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10

राजस्थान अपील प्राधिकरण
जयपुर

वादीगण के परिवार का सजरा भी वादपत्र में प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजीयात बाली रावल गुरु जोत रावल निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ की खुद काशत कृषि आराजीयात थी। बाली रावल गुरु जोत रावल की मृत्यु ग्राम कोटडा में दिनांक 09.08.1999 को हुई। उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजीयात प्रारम्भ से ही बाली रावल गुरु जोत रावल की कब्जे काशत उपयोग उपभोग में रही एवं बाली रावल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि आराजीयात बाली रावल के वारिसान रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण के कब्जे काशत व उपयोग उपभोग में बिना किसी बाधा के लगातार चली आ रही है। नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.07.1960 को ग्राम पंचायत पारडी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण को स्वीकृत कर वादग्रस्त कृषि आराजीयात पारसनाथ गुरु बाली रावल के नाम दर्ज कर दी। उक्त कृषि आराजीयात जो दर्ज की गई उसमें दर्शाया गया कि जबानी वसीयत से बाली रावल गुरु जोत रावल की खुदकाशत भूमि में से 54 बीघा 5 बिस्वा भूमि पारसनाथ गुरु बाली रावल को बाली रावल के चले के रूप में प्रदान की गई। जबकि बाली रावल ने कभी किसी को चेला नहीं रखा और न ही कोई जबानी वसीयत या लिखित वसीयत की गई। बाली रावल ने अपने जीवनकाल में न तो कभी पारसनाथ को चेला रखा न ही कोई जबानी वसीयत की। जबकि विधि विरुद्ध जबानी वसीयत दर्शाकर उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो नामान्तरण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से ही शून्य है। कानूनी रूप से जबानी वसीयत का न तो कोई अस्तित्व होता है और न ही अमल में लाई जा सकती है। वसीयत व्यक्ति के जीवनकाल में अमल में नहीं लाई जाकर उसकी मृत्यु के बाद ही अमल में लाई जा सकती है। बाली रावल की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 को हुई जबकि उक्त शून्य नामान्तरण गलत रूप से दिनांक 31.08.1960 को बाली रावल के जीवनकाल में ही खोल दिया गया। जिसकी जानकारी न तो बाली रावल को थी और न ही उसके वारिसान को हुई। वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 बाली रावल के वारिसान हैं। बाली रावल ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना चेला नहीं रखा। नामान्तरण खोले जाने के समय बाली रावल की आयु 35 वर्ष के लगभग थी उक्त छोटी आयु में कोई व्यक्ति किसी को चेला नहीं रखता है और न ही रखने की सोचता है। बाली रावल स्वयं शादीशुदा थे एवं किसी प्रकार का चेला रखने की आवश्यकता खातेदार बाली रावल को नहीं थी एवं जिस पारसनाथ को नाबालिग चेला बताकर नामान्तरण खोला गया वह नामान्तरण अवैध, शून्य प्रभावहीन व्यर्थ एवं निरर्थक है। पारसनाथ ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत व फर्जी तरीके से नामान्तरण पारसनाथ गुरु बाली रावल के नाम दर्ज करवा दिया। उक्त भूमि बाली रावल की खुद काशत कृषि आराजीयात थी जिसके वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वारिसान होने से

उत्तराधिकारी है। नामान्तरण संख्या 16 जो ग्राम पंचायत पारडी द्वारा स्वीकृत किया गया वह प्रारम्भ से ही निरर्थक व शून्य है जिसे अलग से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। विधिक रूप से जबानी वसीयत बिना हस्ताक्षरित वसीयत व बिना लिखित वसीयत का कोई महत्व नहीं है, जो नामान्तरण खोला गया वह विधिक रूप से शून्य निरस्तकरणीय नामान्तरण है।

वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 के पिता बाली रावल व उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 की उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। अन्त में उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 का नाम उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध में ग्राम पंचायत पारडी द्वारा खोले गए नामान्तरण संख्या 16 को निरस्त किया जाकर शून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वह वादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.11.2016 नियत की गई। दिनांक 07.11.2016 को भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी नियत की गई। दिनांक 22.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील होने से व प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से आगामी तारीख पेशी नियत की गई व उक्त पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 16.05.2018 वास्ते तामील प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट नियत की गई। उससे पूर्व रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण ने दिनांक 19.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन नोटिस अखबार में छाया कराना चाहते हैं। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की तामील अखबार में छाया करने का आदेश पारित किया जिस पर रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण ने सम्मन नोटिस प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.04.2018 को छाया किया गया। व उक्त सम्मन नोटिस छाया की प्रति अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुई


राजस्व अपील प्राधिकारी
विनीतगढ़ (राज)

जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2018 को नियत की गई जिसमें बिना किसी साक्ष्य सबूत के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोंडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपडित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन था। दिनांक 18.11.2020 को अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने पत्रावली में लिखित बहस प्रस्तुत की व पत्रावली रेस्पोंडेन्टगण की बहस में विचाराधीन थी। पत्रावली के बहस में विचाराधीन रहते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 ने राजस्व मण्डल राजस्थान में पत्रावली मुतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा मुतकिली प्रार्थना पत्र क्रमांक 4433/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 09.04.2021 को निर्णित किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को मुतकिल की जाकर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधिकारिता प्रदान की गई।

इस न्यायालय द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति ली गई। उभयपक्षों की पत्रावली में लिखित बहस व मौखिक बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय अंतिम नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली में आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां जो वर्ष 2014 से 2065 तक की हैं, प्रस्तुत की हैं। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही होकर निर्णय पारित हुआ है। जिससे न्यायहित में अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41

नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज जो प्रकरण से सुसंगत होने से रेकॉर्ड पर लिया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में लिखित बहस प्रस्तुत की व वक्त मौखिक बहस निवेदन किया कि बाली रावल गुरु जोत रावल की विवादित कृषि आराजीयात खुद काशत की थी। नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.07.1960 को स्वीकृत हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण मे पारसनाथ गुरु बाली रावल के नाम दर्ज की है व उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात अपीलांटगण के पिता पारसनाथ के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी मे दिनांक 31.07.1960 से चली आ रही है। उक्त कृषि आराजीयात से रेस्पोंडेन्टगण वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा रेस्पोंडेन्टगण वादीगण का उक्त आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काशत व उपयोग उपभोग नहीं रहा है। उक्त कृषि आराजीयात बाली रावल के चेले पारसनाथ को चेले के रूप मे दी थी तथा इसके नामान्तरण मे जालसाजी कर जबानी वसीयत शब्द बाद मे लिखा गया है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण के पिता का सन 1960 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा था। उनकी मृत्यु दिनांक 18.05.2018 के पश्चात उक्त कृषि आराजीयात अपीलांटगण के पिता के बजाये अपीलांटगण का नाम दर्ज करवाने के लिए अपीलांटगण राजस्व कर्मचारियों के पास गए तो उन्होने बताया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात एकतरफा मे पारित निर्णय व डिक्री से रेस्पोंडेन्टगण वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई है। रेस्पोंडेन्टगण वादीगण द्वारा गलत वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलांटगण के पिता की तामील हेतु सम्मन नोटिस गलत पते पर भेजा गया । साथ ही ऐसे अखबार मे सम्मन प्रकाशित किया गया जो अपीलांटगण के पिता के यहा नहीं आता है। अखबार मे सम्मन प्रकाशन किये जाने से पूर्व अपीलांटगण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से नही भिजवाया जाकर सीधे ही अखबार मे प्रकाशन किये जाने का आदेश पारित किया है । जिससे अपीलांटगण की प्रोपर तामील नही होने के बावजूद दिनांक 16.05.2018 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य लिये बिना, अपीलांटगण की बिना तामील के व अपीलांटगण को बिना सुने एकतरफा मे निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण रेस्पोंडेन्टगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। फिर भी कब्जेयाबी का वाद लाये बिना धारा 88, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का वाद चलने योग्य नही होने के बावजूद धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का वाद स्वतः सिद्ध नहीं होता है और न ही कब्जे के सम्बन्ध मे बिना शहादत के कोई वाद निर्णित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति मे वादीगण रेस्पोंडेन्टगण

राजस्व अपील
दिल्ली न्यायालय
दिल्ली न्यायालय
दिल्ली न्यायालय

द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वादीगण रेस्पोजेन्टगण का वाद निरस्त किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोजेन्टगण के वादपत्र को स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोजेन्टगण वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 को हो गई है जबकि वादीगण रेस्पोजेन्टगण की ओर से वादपत्र सन् 2016 में अर्थात् 17 वर्षों बाद प्रस्तुत किया है। अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक से आज तक उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के नामान्तरण में कांटाछट की जाकर जबानी वसीयत शब्द बाद में जोड़ा गया है। वादीगण रेस्पोजेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1960 में खोले गए नामान्तरण को चुनौती देते हुए यह घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त नामान्तरण से कोई आपत्ती है तो ऐसे नामान्तरण के विरुद्ध अपील करना आवश्यक था। ऐसी अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रवण योग्य है। एवं यदि कोई नामान्तरण तहसीलदार द्वारा खोला गया है तो ऐसी स्थिति में अपील जिला कलक्टर द्वारा श्रवण योग्य है। परन्तु किसी भी स्थिति में नामान्तरण के विरुद्ध व कब्जेदार के विरुद्ध 55 वर्षों के बाद प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि कब्जेयाबी का वाद केवल 12 वर्षों में ही लाया जा सकता है जिस कारण वादीगण ने जानबूझकर कब्जेयाबी के तथ्य को छुपाया है तथा कब्जेयाबी के सम्बन्ध में कोई सहायता वादीगण द्वारा नहीं चाही गई है, जिससे रेस्पोजेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों के समर्थन में अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया। अन्त में अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्टगण संख्या 5 व 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोजेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत केम्प में रखी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण रेस्पोजेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण रेस्पोजेन्टगण को ख़ातेदार घोषित किये जाने व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम

अपीलांतगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वक्त नामान्तरण कब्जा नहीं था और न ही वर्तमान में अपीलांतगण प्रतिवादीगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त है। अपीलांतगण प्रतिवादीगण के कथनानुसार यदि नामान्तरण में जबानी वसीयत शब्द बाद में जोड़ा गया है तो अपीलांतगण प्रतिवादीगण के पिता पारसनाथ के नाम उक्त कृषि आराजीयात का नामान्तरण खोले जाने का आधार क्या है, इस तथ्य को अपीलांतगण प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही उक्त तथाकथित जबानी वसीयत के आधार पर किया गया हस्तांतरण सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के विरुद्ध है। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। बाली रावल की मृत्यु के कारण वादीगण रेस्पोंडेन्टगण को उक्त आराजीयात की घोषणा की आवश्यकता होने पर वादीगण रेस्पोंडेन्टगण की ओर से वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। अन्त में अपील अपीलांतगण प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 व 13 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांतगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 10 वादीगण ने अपीलांतगण के पिता पारसनाथ व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 19.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांतगण के पिता पारसनाथ की तामील नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन नोटिस अखबार में छया किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया। अपीलांतगण के पिता पारसनाथ का निवास स्थान भोपालसागर तहसील भोपालसागर अंकित करते हुए सम्मन नोटिस जारी किया गया।


कि अपीलांटगण का संयुक्त परिवार होकर अपीलांटगण व उनके पिता सेंती चित्तौड़गढ़ में विगत कई वर्षों से निवासरत है। यहां तक कि निर्णय के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 पारसनाथ की मृत्यु हुई है जो भी सेंती चित्तौड़गढ़ में ही हुई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 पारसनाथ की प्रोपर तामील होना नहीं पाया जाता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2018 को तामील हो जाना मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण के पिता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बिना साक्ष्य सबूत के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि सम्मत नहीं होने से व अपीलांटगण प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिया गया है उक्त दस्तावेजों का पुनः परीक्षण किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ प्रकरण संख्या 63/2016 राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण प्रतिवादी का जवाबदावा लिया जाकर, तनकीयात कायम की जाकर, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, अजसरे, तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।




(हस्मिदह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़(राज0)